>

Title: Regarding the alleged objectionable remark about women by the Chairperson of the National Commission for Women.

श्रीमती दर्शना जरदोश : वैसे तो गिरिजा जी भी बैठी हुई थीं और काफी महिला सदस्य भी यहां पर उपस्थित हैं जो मेरी बात से सहमत होंगे। पूरी आबादी के 50 प्रतिशत तो हैं और 33 प्रतिशत रिजर्वेशन के बगैर हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए उन्हीं महिलाओं की आवाज यहां पहुंचाने के लिए हम लोग यहां खड़े हुए हैं।

आज मैं ऐसे गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जो अपने आप में एक गंभीर विषय है और मेरा मानना है कि सरकार को ऐसे विषय पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। हाल ही में एक टी.वी. चैनल के इंटरव्यू में केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत महिला आयोग की अध्यक्षा.. *ने समग्र स्त्री जाति को लज्जित किया है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : नाम नहीं लीजिए। केवल अध्यक्ष कहिए।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती दर्शना जरदोश : उन्होंने खुले तौर पर यह कहा कि सैक्सी शब्द अपमानवाचक नहीं है और किसी स्त्री को उससे लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। दुख की बात यह है कि महिला आयोग की चेयरपर्सन का यह मत है जबकि केन्द्र सरकार यूपीए की अध्यक्षा महिला हैं और लोक सभा अध्यक्षा एक महिला को बनाया गया है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : दर्शना जी, मैं थोड़ा सा आपको टोक रहा हूं। अध्यक्षा ने अपना स्टेटमेंट तुंत वापस ले लिया।

श्रीमती दर्शना जरदोश : नहीं, फिर से 15 दिन के बाद जो उन्होंने यह स्टेटमेंट कर दिया था और हम लोगों ने कृष्णा तीरथ जी को स्मृति ईरानी जो हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और मैं भी जनरल सैक्रेटरी हूं, हमने फिर से एक लैटर उनको लिखा है। उन्होंने इसी स्टेटमेंट के ऊपर फेरबदल कर दिया है और उनके सरकार द्वारा नियुक्त महिला आयोग की महिला अध्यक्षा जिनका दायित्व है कि वे महिलाओं की मानहानि, उत्पीड़न जैसे मामलों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए महिलाओं की सहायता करें लेकिन शर्म की बात है कि केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त महिला आयोग की महिला ने ही महिला को घोर अपमानित किया है। डिक्शनरी में अगर इस शब्द का अर्थ देखा जाए तो वह शब्द मैं यहां बोलना उचित नहीं समझती। दुख की बात यह है कि सरकार की ओर से अभी तक उसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं किया गया है कि यह सरकार की राय है या सरकार उनके मत से सहमत है या असहमत है? देश की आधी आबादी सरकार का मत जानना चाहती है क्योंकि हमारे पुर्खों ने कहा है: मौनम सम्मति सूचनम्। यानी मौन सम्मति का सूचक है। यदि सरकार असहमत है तो देश की महिलाओं से उन्हें माफी मांगने को कहते हुए उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए क्योंकि हमारा देश सीता, गंगा और गायत्री को पूजता है। जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं पर देवताओं का वास रहता है। आज उनके ऐसे वक्तव्य की वजह से मां, बहनों और बेटियों पर चौराहे पर खड़े होकर सीटी बजाने वाले मजनुओं एवं लफंगों की हिम्मत बढ़ी है। इसी वर्ष विश्व महिला दिवस के ऊपर दिल्ली में भी ऐसी ही घटना हुई जहां एक लड़की की हत्या हो गई थी। दिल्ली को तो वैसे भी असुरक्षित माना गया है और मैं पूरे महिला मोर्चा की ओर से और यहां बैठी सभी महिला सांसदों की ओर से यह मांग करती हूं कि यदि ऐसा ही रहा और सरकार मौन रही तो हम यह समझेंगे कि सरकार का भी यही मत है। मेरा आग्रह है कि इस सदन में तुंत वक्तव्य देने हेतु एवं संबंधित व्यक्ति का इस्तीफा देने हेतु आप आग्रह करें।

20.00 hrs.